समक्ष - एम.एम. कुमार, जे

मलखान सिंह और अन्य,– वादी/अपीलकर्ता

बनाम

दीप चंद और अन्य - प्रतिवादी

R.S.A. No. 1527 of 1999

19 जनवरी 2005

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908– धारा 100 और 103–प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में उसके पिता द्वारा झेले गए फैसले और डिक्री के आधार पर इंतकाल की मंजूरी–परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 2 पिता के द्वारा ली गयी एक अन्य फैसले और डिक्री के आधार पर प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में इंतकाल की मंजूरी - प्रतिवादी 2 द्वारा अपीलकर्ताओं के पक्ष में बैनामा और एक स्थायी पट्टानामा का निष्पादन - राजस्व अधिकारियों ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में उत्परिवर्तन को मंजूरी देने से इनकार कर दिया - इसे चुनौती - नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने इस दलील पर अपीलकर्ताओं के मुकदमे को खारिज कर दिया कि वे प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में पारित निर्णय और डिक्री में उल्लिखित भूमि के साथ मुकदमे की भूमि का संबंध स्थापित करने के लिए विफल रहे हैं - नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष - क्या उच्च न्यायालय के पास तथ्य के ऐसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र है - **अभिनिर्णित** - हाँ - यदि इस तरह के निष्कर्ष विकृति से ग्रस्त हैं - नीचे की अदालतें दस्तावेजों की सराहना करने में विफल रही हैं - मुकदमा भूमि और प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में पारित

निर्णय और डिक्री में उल्लिखित भूमि के बीच सामान्य भूमि की पहचान दिखाने वाले दस्तावेजी साक्ष्य - के निचली अदालतों ने दस्तावेजों में की गई टिप्पणियों के विपरीत निष्कर्ष- अपील की अनुमति दी और वादी-अपीलकर्ताओं के मुकदमे पर फैसला सुनाते समय नीचे की दोनों अदालतों के निष्कर्षों को खारिज कर दिया।

अभिनिर्णित उच्च न्यायालय आमतौर पर नीचे के दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा । हालाँकि, तथ्यों के ऐसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की उच्च न्यायालय की शक्ति पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि निष्कर्ष विकृत पाए जाएं। यदि कोई दस्तावेज़ विचार-विमर्श से छूट गया है या गलत पढ़ा गया है और निष्कर्ष ख़राब हैं तो यह कानून का एक वास्तविक प्रश्न होगा। एक बार जब यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि निचली अदालतें दस्तावेजों की सराहना करने में विफल रही हैं और उन दस्तावेजों का उल्लेख नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे निष्कर्ष निकले हैं जो दस्तावेजों में की गई टिप्पणियों के विपरीत हैं तो ऐसे निष्कर्ष को विकृत माना जाएगा।

(पैरा 11 और 13)

इसके अलावा निर्धारित किया गया कि निचली अदालतें इस तथ्य पर विचार करने में विफल रही हैं कि 20 सितंबर, 1984 के फैसले और डिक्री को प्रतिवादी संख्या 1 ने आयत क्रमांक 116 (0–13M) के संबंध में राजस्व अधिकारियों से इंतकाल कराया गया । प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दिए गए बयान के आलोक में उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए।

अपनी जिरह में उसने स्वीकार किया है कि उसने आयत क्रमांक 116 में एक कमरे का निर्माण किया है। दिनांक 20 सितम्बर 1984 के निर्णय एवं डिक्री में राजस्व संख्या के स्थान पर सीमाओं का उल्लेख किया गया क्योंकि उस समय उन्हें संख्या की जानकारी नहीं थी। जाहिर तौर पर उपर्युक्त कथन के आधार पर आयत क्रमांक 116 (0-13 M) के संबंध में इंतकाल को मंजूरी दी गई है, जैसा कि PW 9/A से स्पष्ट है। हालाँकि दस्तावेज़ों का उल्लेख नीचे के न्यायालयों द्वारा किया गया है, लेकिन इंतकाल Ex. PW 9/A दिनांक 2 दिसंबर, 1988 को पढ़कर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है। पैराग्राफ 1, 4(ii) और 5 में 20 सितंबर, 1984 के फैसले और डिक्री और 2 दिसंबर, 1988 के इंतकाल संख्या 1176 का संदर्भ दिया गया है। यहां तक कि एक मुद्दा भी उपर्युक्त दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया है। हालाँकि, उपर्युक्त दस्तावेज़ को पढ़ने में एक बुनियादी त्रुटि हुई है जिसके परिणामस्वरूप वादी-अपीलकर्ता के साथ स्पष्ट अन्याय हुआ है क्योंकि नीचे के न्यायालयों ने एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि भूमि की पहचान स्थापित नहीं की गई है जबकि फॉर्म में पर्याप्त सबूत Ex. PW 9/A हैं जो कि आयत क्रमांक 116 (0–13M)(गैर मौरूसी आबादी भूमि)के संबंध में इंतकाल की मंजूरी को दर्शाता है। और उसी भूमि पर वादी-अपीलकर्ताओं द्वारा दावा किया गया है। इसलिए, मुद्दे नंबर 1 पर नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के निष्कर्ष को रद्द किया जाना चाहिए।

(पैरा 20)

अधिवक्ता विकास कुमार- अपीलकर्ताओं की ओर से

राजीव शर्मा, अधिवक्ता- प्रतिवादियों की ओर से

निर्णय

एम.एम. कुमार, जे.

(1) यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षिप्तता के लिए संहिता) की धारा 100 के तहत दायर की गई वादी की दूसरी अपील है, जिसमें नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों को चुनौती दी गई है। एक संक्षिप्त प्रश्न जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या भूमि की पहचान से संबंधित मुद्दे पर नीचे के न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष इंतकाल Ex. PW 9/A जो स्पष्ट रूप से वाद भूमि की पहचान स्थापित करता है उदाहरण के रूप में श्रेणीबद्ध दस्तावेजी साक्ष्य के कारण खराब हो गए हैं।

संक्षिप्त तथ्य:

(2) एक जग्गन मालिक था और खेवट संख्या 11-12 खतौनी संख्या 17-18, आयत क्रमांक 116 (0-13 M), रकबा 1/2 हिस्सेदारी गैर मुमकिन आबादी और खेवट संख्या 10 खतौनी संख्या 14 आयत क्रमांक 117 (1-3 M) जो की गांव मंधावली, तहसील बल्लबगढ़ में स्थित है , की सीमा तक भूमि के सह-हिस्सेदार/संयुक्त मालिक के रूप में कब्जे में था। उनका खचेरू नाम का एक बेटा था । जग्गन को 30 अक्टूबर, 1980 को उनके पक्ष में एक फैसले और डिक्री का सामना करना पड़ा (Ex. P3 and P4)। निर्णय और डिक्री Exs. P.3, और P.4 के

कारण बेटे, खचेरू, के पक्ष में इंतकाल को मंजूरी मिल गई जो की Ex. P.6 है । इसके बाद जग्गन को फिर से पूर्व न्यायाधीश के फैसले और डिक्री P.8, और P.9 दिनांक 20 सितंबर, 1984 जो की प्रतिवादी दीप चंद के पक्ष में, का सामना करना पड़ा, जिसके कारण प्रतिवादी पक्ष में इंतकाल Ex. PW 9/A दिनांक 2 दिसंबर, 1988 की मंजूरी मिल गई।

(3) उसके अधिकार के आधार पर जो Ex. P3 और P4 दिनांक 20 अक्टूबर, 1980 के निर्णय और डिक्री से प्राप्त हुआ, खचेरू ने वादी-अपीलकर्ताओं के पक्ष में 99 वर्षों के लिए एक बैनामा(Ex. P2) और एक स्थायी पट्टानामा(Ex. P1) निष्पादित किया, जो 30 नवंबर, 1993 को दिनांकित है । जब वादी-अपीलकर्ता ने अपने पक्ष में इंतकाल को मंजूरी देने की प्रार्थना के साथ राजस्व अधिकारियों से संपर्क किया तो इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि इंतकाल Ex. PW 9/A दिनांक 2 दिसंबर, 1988 दीप चंद प्रतिवादी के पक्ष में दर्ज किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वादी/अपीलकर्ता, जो खचेरू से मुकदमे की भूमि के विक्रेता हैं, ने इस आशय की घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया कि निर्णय और डिक्री(Ex. P8 and P9) दिनांक 20 सितंबर, 1984 के साथ प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत इंतकाल Ex. PW 9/A दिनांक 2 दिसंबर, 1988 अमान्य था और वे वादी-अपीलकर्ताओं पर बाध्यकारी नहीं थे। वाद में, वादी-अपीलकर्ता द्वारा मूल तर्क के समर्थन में कई दलीलें दी गईं कि 1984 के सिविल सूट नंबर 52 में सीनियर सब जज, फरीदाबाद द्वारा 20 सितंबर, 1984 को पारित निर्णय और डिक्री और परिणामी इंतकाल Ex. PW 9/A दिनांक 2 दिसंबर, 1988 अमान्य था

और यह उनके अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं था। मुख्य आधार यह था कि खचेरू के पिता जग्गन को पहले ही 30 अक्टूबर, 1980 को खचेरू प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निर्णय और डिक्री(Ex. P3 and P4) का सामना करना पड़ा था एवं इंतकाल क्रमांक 1003 Ex.P 6 को 29 दिसंबर, 1986 को उनके पक्ष में मंजूरी दे दी गई थी। यह भी कहा गया था कि एक बार 30 अक्टूबर, 1980 के फैसले और डिक्री को जग्गन ने खचेरू के पक्ष में लिया था, तो उन्हें एक और फैसले और डिक्री (Ex. P8 और P9) का सामना नहीं करना पड़ सकता था। आगे दावा किया गया कि पहले पारित निर्णय और डिक्री बाद में पारित निर्णय और डिक्री पर लागू होगी। उस आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत इंतकाल Ex.PW.9/A को भी चुनौती दी गई थी।

(4) जवाब दावे में, प्रतिवादी नंबर 1 ने वादी-अपीलकर्ता द्वारा किए गए दावों का व्यापक रूप से खंडन किया। यह दावा किया गया कि 20 सितंबर, 1984 के निर्णय और डिक्री (Ex. P8 और P9) और 2 नवंबर 1988 का इंतकाल वादी-अपीलार्थी की जानकारी में था और इसलिए, वे मुकदमे में दावा की गई राहत के हकदार नहीं थे। वादी-अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर किए गए लिखित बयान के लिए एक प्रतिकृति भी दायर की गई थी जिसमें वादी में किए गए दावे को दोहराया गया था। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए और उन पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

(5) पक्षों की दलीलों के आधार पर पांच मुद्दे तय किए गए। हालाँकि, मेरे सामने उठाए गए विवाद को तय करने के लिए मुद्दा नंबर 1 महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है:

> "क्या 1984 के सिविल सूट नंबर 52 में पारित सिविल डिक्री दिनांक 20 सितंबर, 1984 और प्रासंगिक रिकॉर्ड असर संख्या 1176 में उक्त डिक्री के अनुसरण में स्वीकृत इंतकाल शून्य हैं? OPP."

ट्रायल कोर्ट और अपीलीय कोर्ट के विचार:

(6) ट्रायल कोर्ट ने वादी-अपीलकर्ताओं के मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यद्यपि वादी-अपीलकर्ताओं ने अपने विक्रेता के पक्ष में मुकदमे की भूमि के संबंध में 30 अक्टूबर, 1980 के निर्णय और डिक्री के साथ-साथ और बैनामा (Ex. P1) और एक स्थायी पट्टानामा (Ex. P2) दिनांक 30 नवंबर, 1993 को भी साबित कर दिया , लेकिन वे मुकदमे की भूमि को 20 सितंबर, 1984 के निर्णय और डिक्री (Ex. P.8 और P.9) और इंतकाल Ex.PW.9/A के साथ जोड़ने में विफल रहे हैं। उस आधार पर दावा की गई राहत को अस्वीकार कर दिया गया था, हालांकि यह स्वीकार किया गया था कि यदि वादी-अपीलकर्ता उपरोक्त दो दस्तावेजों के साथ मुकदमे की भूमि को जोड़ने में सक्षम थे, तो उनका मुकदमा डिक्री के योग्य था। उपरोक्त मुद्दे पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-

'वादी ने निस्संदेह खचेरू के पक्ष में वाद भूमि के संबंध में 30 अक्टूबर, 1980 की सिविल कोर्ट की डिक्री , बैनामा और एक स्थायी पट्टानामा को साबित कर दिया है, जो Ex. P2 and P 1 हैं चूँकि इन दस्तावेज़ों में वाद भूमि के शब्दशः अनुरूप होने का उल्लेख है, जबकि चूँकि वाद की संपत्ति की डिक्री दीप चंद के पक्ष में हुई है, - दिनांक 20 सितंबर, 1984 के फैसले से वाद भूमि का संबंध नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह सिविल कोर्ट की डिक्री संबंधित है वाद भूमि से और, इसलिए, चूंकि वादी संबंध बनाने में विफल रहे हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि चूंकि वाद भूमि के संबंध में जग्गन द्वारा पहले ही खचेरू के पक्ष में एक डिक्री निष्पादित की जा चुकी थी, इसलिए बाद की डिक्री को उसी द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सका। उसी जमीन को लेकर जग्गन दीपचंद के पक्ष में था। केवल यदि वादी द्वारा 20 सितंबर, 1984 के सिविल कोर्ट डिक्री में उल्लिखित संपत्ति का संबंध वाद भूमि के साथ स्थापित किया जा सकता है, तो यह कहा जा सकता है कि बाद की डिक्री अमान्य है। चूंकि कोई संबंध नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सिविल कोर्ट की 20 सितंबर, 1984 की डिक्री और उसके अनुसरण में स्वीकृत उत्परिवर्तन अमान्य है क्योंकि यह वाद भूमि के अलावा किसी अन्य संपत्ति से संबंधित हो सकता है, हालांकि, बैनामा और एक स्थायी पट्टानामा Ex. P2 और Ex. P1 वाद भूमि से संबंधित पूरी तरह से वैध होंगे क्योंकि खचेरू

30 अक्टूबर 1980 की सिविल डिक्री के संबंध में वाद भूमि को वादी के पक्ष में स्थानांतरित करने का हकदार था।

(7) वादी-अपीलकर्ताओं द्वारा आदेश XLI नियम 27 C.P.C. के तहत एक आवेदन के साथ दायर की गई अपील। विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को इस आधार पर बरकरार रखते हुए खारिज कर दिया गया था कि वादी-अपीलकर्ताओं ने संपत्ति के साथ मुकदमे के बीच संबंध को ठीक से साबित नहीं किया था जो कि 20 सितंबर, 1984 के फैसले और डिक्री (Ex. P8 और P9) और इंतकाल Ex.PW.9/A दिनांक 2 नवंबर, 1988 का विषय था। स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य जोड़ने का आवेदन भी खारिज कर दिया गया। इस विषय में विद्वान अपीलीय न्यायालय के विचार को पैरा 11, 12 और 13 से समझा जा सकता है जो इस प्रकार है:-

'अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति के माध्यम से अतिरिक्त साक्ष्य के लिए आदेश 41 नियम 27 के तहत एक आवेदन भी दायर किया है। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि निचली अदालत के फैसले के आलोक में वे वाद की संपत्ति को 20 सितंबर 1984 के डिक्री में उल्लिखित संपत्ति के साथ जोड़ने में विफल रहे, जो चुनौती के अधीन है। आवेदन में उनकी प्रार्थना है कि स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति द्वारा 20 सितंबर 1984 के डिक्री में उद्धृत वाद संपत्ति का सीमांकन और पता लगाना आवश्यक है।

चूंकि, अपीलकर्ता/वादी अपने उचित परिश्रम के बावजूद मुकदमे की संपत्ति को 20 सितंबर, 1984 के डिक्री में शामिल संपत्ति के साथ जोड़ने में असफल रहे, उन्होंने प्रार्थना की कि खसरा क्रमांक 116 में शामिल प्रश्न में संपत्ति का सीमांकन करने के लिए एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया जाए।

इस न्यायालय में दायर दिनांक 18 जनवरी, 1999 के अपने आवेदन में अपीलकर्ताओं द्वारा उल्लिखित आधारों का एक मात्र अवलोकन यह दर्शाता है कि विद्वान निचली अदालत के निष्कर्ष को उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। उनके द्वारा वाद संपत्ति को 20 सितंबर 1984 की चुनौती के तहत डिक्री में शामिल संपत्ति से नहीं जोड़ा जा सका।

प्रतिद्वंद्वी विवाद:

(8) वादी-अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री विकास कुमार ने तर्क दिया है कि आबादी देह गैर मुमकिन भूमि की पहचान दिखाने वाले रिकॉर्ड पर अंतर्निहित साक्ष्य उपलब्ध हैं जो आयत क्रमांक 116 (0–13M) है और यह सूट वाली भूमि और उस भूमि के बीच आम है जो बैनामा(Ex. P2) और एक स्थायी पट्टानामा(Ex. P1) का विषय था में शामिल हैं। विद्वान वकील ने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के Ex. PW9/A पेज 83 पर और प्रतिवादी नंबर 1 दीप चंद का बयान का भी उल्लेख किया है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार इंतकाल Ex. PW9/A दिनांक 2 दिसंबर, 1988 स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि 20 सितंबर, 1984 का निर्णय और

डिक्री आयत क्रमांक 116 (0–13M) जिसे गैर मुमकिन आबादी देह के रूप में वर्णित किया गया है, के संबंध में इंतकाल को मंजूरी देने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। दीप चंद DW1 द्वारा दिए गए बयान का हवाला देते हुए, विद्वान वकील ने बताया कि वाद भूमि की पहचान के संबंध में उनके द्वारा एक स्वीकारोक्ति की गई है जब उन्होंने कहा कि निर्णय और डिक्री दिनांक 20 सितंबर, 1984 Ex. P8 और Ex. P9 आयत क्रमांक 116 (0–13M) के संबंध में है। विद्वान वकील ने मेरा ध्यान वादपत्र के पैरा 1 की ओर भी आकर्षित किया है जिसमें विवादित भूमि को गैर मुमकिन आबादी के रूप में वर्णित किया गया है और यह आयत क्रमांक 116 (0–13M) में शामिल है। वादपत्र के पैरा 4 और 5 में वादी-अपीलकर्ताओं की दलीलों का हवाला देते हुए, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि इंतकाल संख्या 1176, दिनांक 2 दिसंबर, 1988 Ex. PW9/A का मात्र अवलोकन इंगित करता है कि यह आयत क्रमांक 116 (0–13M) ग़ैर मुमकिन आबादी के संबंध में है । विद्वान वकील ने मुद्दे नंबर 1 पर ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गए विचारों का उल्लेख किया है और तर्क दिया है कि 20 सितंबर, 1984 के फैसले और डिक्री को पूरी तरह से नहीं पढ़ा गया है या गलत पढ़ा गया है। Ex. PW9/A इंतकाल क्रमांक 1176 दिनांक 2 नवम्बर 1988 के आलोक में Ex. P.8 एवं P.9. जो स्पष्ट रूप से भूमि की पहचान स्थापित करता है और इसे मुकदमे की भूमि से जोड़ता है जैसा कि वादपत्र में वर्णित है।

(9) अपने तर्क को पुष्ट करते हुए, वादी-अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह भी बताया है कि एक बार इस न्यायालय ने यह विचार कर लिया है कि निष्कर्ष विकृत हो गए हैं क्योंकि निचली अदालतों में Ex. PW9/A इंतकाल में प्रविष्टि की सराहना नहीं की गई है, इस अदालत के लिए संहिता की धारा 100 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में कोई बाधा नहीं **है। उन्होंने कुलवंत कौर और अन्य बनाम गुरदयाल सिंह मान और अन्य**[1] और **यादराव दाजीबा श्रवणे बनाम नानीलाल हरकचंद शाह और अन्य**[2] के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ दिया है। विद्वान वकील ने धारा 103, 107 और आदेश XLI नियम 43 के प्रावधानों का भी संदर्भ दिया है और प्रस्तुत किया है कि यह न्यायालय पूर्ण न्याय प्रदान करने और निष्कर्ष को रिकॉर्ड करने के लिए व्यापक शक्तियों से सुसज्जित है, जिसका प्रयोग सिविल न्यायालय जैसे मूल क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय कर सकते हैं। उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने **अश्विन कुमार के. पटेल बनाम उपेन्द्र जे. पटेल**[3] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **श्रीनिवासन बनाम थिलाकन**[4] के मामले में केरल उच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया है।

(10) प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील श्री राजीव शर्मा ने जोरदार तर्क दिया है कि वादपत्र में किसी भी कमरे या निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है जो 20 सितंबर, 1984 के निर्णय और

---

[1] 2001(4) S.C.C. 262
[2] 2002(6) S.C.C.404
[3] 1999(3) S.C.C. 161
[4] 2003(3) C.C.C. 294

डिक्री (Ex. P8 और P9) का विषय है। उन्होंने मेरा ध्यान ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के पृष्ठ 39 पर उल्लिखित निर्णय की ओर आकर्षित किया है और तर्क दिया है कि निर्णय और डिक्री के शीर्षक में दी गई सीमाएं स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक घोषणा की मांग की गई थी कि वह गाँव मंझवाली, तहसील बल्लबगढ़, जिला फ़रीदाबाद की आबादी में दो कमरों और खुली जगह वाले एक आवासीय पक्के मकान का मालिक था। उपर्युक्त आधार पर, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि निचली अदालतों द्वारा यह सही माना गया है कि वादी-अपीलकर्ता निर्णय और डिक्री (Ex. P8 और P9) के साथ मुकदमे की भूमि का कोई भी संबंध स्थापित करने में विफल रहे हैं। विद्वान वकील ने संहिता के आदेश XLI नियम 27 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य जोड़ने के लिए आवेदन का भी उल्लेख किया है, जिसमें वादी-अपीलकर्ता निर्णय और डिक्री (Ex. P8 और P9) के साथ विवाद में भूमि का संबंध स्थापित करने में विफल रहे हैं। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने **मैसर्स गोयल इंजीनियर (इंडिया) बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड**[5] के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है और तर्क दिया है कि एक बार रिकॉर्ड किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष हो गये तो नीचे की दोनों अदालतों को इस अदालत को सबूतों की दोबारा सराहना करके उन निष्कर्षों को अस्थिर करने का तरीका नहीं अपनाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बताया कि इस अपील में जिस तर्क को उठाने की मांग की गई है, वह निचली अदालतों के समक्ष कभी नहीं उठाया

[5] 2003(4) R.C.R. (Civil) 627

गया है और इसलिए पहली बार उक्त तर्क को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने मेरा ध्यान **मेसर्स गोयल इंजीनियर** (supra) के मामले में फैसले के पैरा 4 में उद्धृत विभिन्न निर्णयों की ओर आकर्षित किया है।

(11) उठाए गए विवाद को शुरू करने से पहले इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का दायरा निर्धारित करना आवश्यक होगा जैसा कि संहिता की धारा 100 के तहत परिकल्पित किया गया है। यह सच है कि यह न्यायालय आम तौर पर नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, हालांकि, तथ्यों के ऐसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की इस न्यायालय की शक्ति पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि निष्कर्ष विकृत पाए जाएं। उपर्युक्त सिद्धांतों को सुप्रीम कोर्ट ने **हफ़ज़त हुसैन बनाम अब्दुल मजीद और अन्य**[6] के मामले में दोहराया है। फैसले के पैरा 8 में उनके आधिपत्य ने तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की अनुमति की बात की है और निम्नानुसार पालन करने के लिए आगे बढ़े हैं:-

> "हमने दोनों पक्षों की ओर से अपील करने वाले विद्वान वकील की दलीलों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह बताया गया है कि रिकॉर्ड पर सामग्री की उचित सराहना पर ट्रायल जज के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों को

[6] (2001) 7 S.C.C. 189

द्वितीय अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय द्वारा परेशान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही, यह सार्वभौमिक रूप से और हमेशा लागू होने वाला एक पूर्ण नियम नहीं है क्योंकि इसके अपवादों को भी अक्सर इस न्यायालय में समान महत्व के साथ इंगित किया गया था, और ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां ऐसी आवश्यकता के बावजूद इस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, यदि दूसरी अपीलीय अदालत ने यांत्रिक रूप से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, यहां तक कि मामले को इस अदालत ने दूसरी अपीलीय अदालत में स्थानांतरित कर दिया है ताकि दूसरी अपील में पार्टियों के दावों को निष्पक्ष रूप से धारा 100 सिविल प्रक्रिया संहिता, के तहत हस्तक्षेप के लिए विचार के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए निपटाया जा सके। इसलिए, यह देखना आवश्यक हो जाता है कि क्या उच्च न्यायालय में विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुमेय सीमाओं का उल्लंघन किया है।"

(12) सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद पाया कि गंभीर अवैधताओं और कमजोरियों के कारण द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप आवश्यक था। न्याय के पूर्ण गर्भपात को रोकने के लिए संहिता की धारा 100 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग भी आवश्यक पाया गया। इस मुद्दे से अब तक प्रासंगिक पैरा 9 में उनके आधिपत्य की टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

"द्वितीय अपीलीय न्यायाधीश विद्वान परीक्षण न्यायाधीश के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायाधीश द्वारा की गई गंभीर कमजोरियों और अवैधताओं को इंगित करने और उजागर करने में सक्षम थे, और ठोस कारणों के साथ, न्याय के पूर्ण गर्भपात को रोकने के लिए उनके हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को न केवल तर्क की विकृति के कारण, बल्कि अनुमानों और रिकॉर्ड पर सामग्री की गलत व्याख्या के कारण भी दूषित पाया गया। दूसरी अपील में फैसले की सावधानीपूर्वक और आलोचनात्मक जांच करने पर, हम अपीलकर्ता के विद्वान वकील से सहमत होने में असमर्थ हैं कि समवर्ती रूप से दर्ज किए गए तथ्य के किसी भी निष्कर्ष को बिना किसी औचित्य के या अभ्यास की सीमाओं का उल्लंघन करके यांत्रिक रूप से हस्तक्षेप किया गया था। उच्च न्यायालय में विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिए गए निष्कर्षों के लिए दिए गए कारणों से इस अपील में हमारे हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाएगी। पार्टियाँ अपनी लागत स्वयं वहन करेंगी।"

(13) यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि कोई दस्तावेज़ विचार से छूट गया है या गलत तरीके से पढ़ा गया है और निष्कर्ष ख़राब हैं तो यह कानून का एक वास्तविक प्रश्न होगा। एक बार जब यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि निचली अदालतें दस्तावेजों

की सराहना करने में विफल रही हैं और उन दस्तावेजों का उल्लेख नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे निष्कर्ष निकले हैं जो दस्तावेजों में की गई टिप्पणियों के विपरीत हैं तो ऐसे निष्कर्ष को विकृत माना जाना चाहिए। इस संबंध में, **कुलवंत कौर** (supra) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्त किए गए विचार प्रासंगिक हैं और अनुपात पैरा 33 से स्पष्ट है जो निम्नानुसार है: -

> "मामले की उपरोक्त रूपरेखा का उल्लेख करते हुए, श्री मेहता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय, कानून के पर्याप्त प्रश्न के अभाव में, निचली अपीलीय अदालत के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जिसके पास अन्यथा जांच और मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र है। श्री मेहता ने तर्क दिया कि वसीयत की संदिग्ध विशेषताएं, केवल तथ्य के प्रश्न हैं जिन पर केवल प्रथम अपीलीय अदालत के स्तर तक ही विचार किया जा सकता है, उससे आगे नहीं और पक्षों द्वारा बनाए गए कानून के किसी ठोस प्रश्न के अभाव में उच्च न्यायालय यदि न्यायालय द्वारा स्वयं ऐसा नहीं बनाया गया है, तो उसे अनुमति देना तो दूर, अपील पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और यह एक हस्तक्षेप है जो पूरी तरह से अनधिकृत है या क्षेत्राधिकार से अधिक है या किसी भी तरह का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। हालाँकि, हम श्री मेहता द्वारा प्रतिपादित इतने व्यापक प्रस्ताव पर सहमति देने की स्थिति में नहीं हैं। न्यायिक दृष्टिकोण न्यायोन्मुख होने के कारण, श्री

मेहता द्वारा बताई गई परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर करने से, न्याय की अवधारणा के विपरीत एक असंगत स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अकेले तकनीकी कारण से उच्च न्यायालय को इस मुद्दे पर निर्णय लेने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि न्याय उन्मुख दृष्टिकोण वर्तमान समय की मांग है। विचाराधीन मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर गहराई से विचार किया है कि क्या वास्तव में रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य ऐसे निष्कर्ष की गारंटी देते हैं - क्या उच्च न्यायालय इस तरह की सराहना में सही था या नहीं - यह पूरी तरह से एक अलग मुद्दा है। लेकिन तथ्य यह है कि दूसरी अपील में क्षेत्राधिकार के प्रयोग के मामले में सबूतों की जांच पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी, यह बहुत व्यापक प्रस्ताव होगा और कानून की बहुत कठोर व्याख्या होगी जो स्वीकार्यता के योग्य नहीं होगी। यदि न्याय की अवधारणा इतनी उचित है, तो हमें कोई कारण नहीं दिखता कि इस तरह के अभ्यास की निंदा क्यों की जाएगी। हालाँकि, यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 से संबंधित किसी भी राय की अभिव्यक्ति के बिना है।

(14) निर्णयों द्वारा यह भी तय किया गया है कि समवर्ती निष्कर्षों में भी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब प्रवेश की प्रकृति में साक्ष्य के एक महत्वपूर्ण टुकड़े को नीचे के न्यायालयों द्वारा

नजरअंदाज कर दिया गया हो। उस संबंध में यादराव देइबा श्रावणे (supra) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा 31 पर भरोसा किया जा सकता है, जो इस प्रकार है :-

> "निर्णय में चर्चा से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजी साक्ष्य और कुछ गवाहों द्वारा दिए गए बयानों पर आधारित किए हैं जिन्हें स्वीकारोक्ति या निष्कर्ष के रूप में माना जा सकता है। यह स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है कि जब तथ्य की अंतिम अदालत का निर्णय दस्तावेजी साक्ष्य की गलत व्याख्या या अस्वीकार्य साक्ष्य पर विचार करने या भौतिक साक्ष्य की अनदेखी पर आधारित होता है, तो दूसरी अपील में उच्च न्यायालय निर्णय में हस्तक्षेप करने का हकदार होता है। यह स्थिति भी अच्छी तरह से स्थापित है कि पार्टियों या उनके गवाहों की स्वीकारोक्ति साक्ष्य के प्रासंगिक टुकड़े हैं और न्यायालयों द्वारा इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए। ऐसी स्वीकृतियों या रियायतों की अनदेखी करते हुए तथ्य की खोज करना कानून की नजर में दोषपूर्ण है और उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील में इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। चूँकि पार्टियाँ कई दशकों से मुकदमेबाजी कर रही हैं, इसलिए रिकॉर्ड बड़े पैमाने पर हैं। जैसा कि फैसले से प्रतीत होता है, उच्च न्यायालय ने उनकी स्वीकार्यता और प्रासंगिकता से संबंधित कानून के आलोक में दस्तावेजी साक्ष्यों पर विस्तृत चर्चा की है।"

(15) सर्वोच्च न्यायालय ने **देवा बनाम सज्जन कुमार**[7] के मामले में भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया है। उनके आधिपत्य की प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

> "7. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति की प्रकृति में साक्ष्य के बहुत महत्वपूर्ण टुकड़े को नीचे की अदालतों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था और इस प्रकार परिसीमा के आधार पर मुकदमा गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था, इसलिए दूसरी अपील में उच्च न्यायालय नीचे की अदालतों के निर्णयों को पलटें के लिए पूर्ण औचित्य था। ।
>
> 8. चूंकि गवाह बॉक्स में प्रतिवादी के कथित प्रवेश की सामग्री और प्रभाव के संबंध में संदेह उत्पन्न हुआ, इसलिए हमने पक्षों को ट्रायल कोर्ट में दर्ज गवाहों के बयानों की अनुवादित प्रतियां प्रदान करने का निर्देश दिया। वकील के पास गवाही की आवश्यक प्रतियां उपलब्ध नहीं थीं। इसलिए, हमने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड की मांग की है, रिकॉर्ड को देखने पर, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के बयान में निहित स्वीकारोक्ति के आधार पर निचली अदालतों के निर्णयों में हस्तक्षेप करना सही था। यह वर्ष 1940 से भूमि के अतिक्रमित हिस्से पर प्रतिकूल कब्ज़ा होने के उनके मामले को स्पष्ट रूप से नकारात्मक करता है।

---

[7] (2003) 7 S.C.C. 481

(16) मेरा यह भी मानना है कि संहिता की धारा 103 इस न्यायालय को तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान करती है यदि ऐसे निष्कर्ष विकृति से ग्रस्त हैं। कुलवंत कौर(supra) के मामले में धारा 103 का हवाला देते हुए इस पहलू पर जोर देते हुए उनके आधिपत्य को पैरा 34 में निम्नानुसार देखा गया है :-

> “बेशक, जहां तक उच्च न्यायालय का संबंध है, धारा 100 ने दूसरी अपील में क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर एक निश्चित प्रतिबंध लगाया है। यह रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 ने ऐसे निश्चित उद्देश्यों के लिए इस तरह का प्रतिबंध लगाया था और चूंकि हमें उस संबंध में आगे की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम विवरण नहीं दे रहे हैं, लेकिन तथ्य यह है कि जबकि यह है सच है कि दूसरी अपील में तथ्य का निष्कर्ष, भले ही गलत हो, आम तौर पर परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन जहां यह पाया जाता है कि निष्कर्ष गलत परीक्षण और मान्यताओं और अनुमानों के आधार पर विकृत हैं और परिणामस्वरूप इसमें विकृति का तत्व शामिल है उसमें, हमारे विचार में इस मुद्दे से निपटने के लिए उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में होगा। हालाँकि, ऐसा केवल तभी होता है जब इस तरह के तथ्य को उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकाश में लाया जाता है और न्याय की अवधारणा की तुलना में विकृति के मुद्दे पर निर्णय भी स्पष्ट होना चाहिए। हालाँकि, यह

कहने की आवश्यकता नहीं है कि विकृति अपने आप में निर्णय लेने योग्य एक महत्वपूर्ण प्रश्न है - विकृति के संबंध में उच्च न्यायालय की ओर से एक स्पष्ट निष्कर्ष की आवश्यकता है। संदर्भ में संहिता की धारा 103 का संदर्भ लें जो इस प्रकार है:-

“103. यदि अभिलेख में का साक्ष्य पर्याप्त हो तो किसी भी द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय ऐसी अपील के निपटारे के लिए आवश्यक कोई विवाद्यक अवधारित कर सकेगा , जो —

(क) निचले अपील न्यायालय द्वारा या प्रथम बार के न्यायालय और निचले अपील न्यायालय दोनों द्वारा अवधारित नहीं किया गया है , अथवा

(ख) धारा 100 में यथानिदृष्टि विधि के ऐसे प्रश्न के विनिश्चय के कारण ऐसे न्यायालय या न्यायालयों द्वारा ग़लत तौर पर अवधारित किया गया है”।

आवश्यकताएँ धारा 103 में निर्दिष्ट हैं और इससे कम कुछ भी इसे धारा 100 के दायरे में नहीं लाएगा क्योंकि विकृति का मुद्दा भी कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के दायरे में आएगा जैसा कि ऊपर देखा गया है। तथ्य की खोज की वैधता को कानून का प्रश्न नहीं कहा जा सकता है, फिर भी हम दोहराते हैं कि उच्च न्यायालय के फैसले में इस आशय का एक निश्चित निष्कर्ष होना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि संहिता की धारा 100 इसका अनुपालन किया जाता है।"

(17) **लीला सोनी बनाम राजेश गोयल**[8] में सुप्रीम कोर्ट को फिर से धारा 100, 101 के दायरे पर अपना विचार व्यक्त करने का अवसर मिला। संहिता की धारा 103. यह देखा गया है कि उच्च न्यायालय तथ्य के प्रश्न पर अपील पर विचार नहीं कर सकता है, भले ही उच्च न्यायालय का मानना हो कि निष्कर्ष गलत हैं या अलग दृष्टिकोण संभव है। हालाँकि, धारा 103 अभी भी इस न्यायालय को किसी भी मुद्दे को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करती है जो दूसरी अपील के निपटान के लिए आवश्यक है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

> "धारा 103 CPC उच्च न्यायालय को किसी भी मुद्दे को निर्धारित करने के लिए अधिकृत करती है जो दूसरी अपील के निपटान के लिए आवश्यक है, बशर्ते कि रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर्याप्त हो, निम्नलिखित दो स्थितियों में से किसी में: (1) जब वह मुद्दा दोनों द्वारा निर्धारित नहीं किया गया हो ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ निचली अपीलीय अदालत या निचली अपीलीय अदालत द्वारा, या (2) जब ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ अपीलीय अदालत या निचली अपीलीय अदालत दोनों ने कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर किसी भी मुद्दे को गलत तरीके से निर्धारित किया हो उचित रूप से सीपीसी की धारा 100 के तहत दूसरी अपील का विषय होगा।"

[8] (2001) 7 S.C.C. 494

(18) यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि दस्तावेज़ की व्याख्या का प्रश्न हमेशा कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएगा जैसा कि **कोचुकक्कडा अबूबकर बनाम अत्ता कासिम**[9] और **सांता कुमारी बनाम लक्ष्मी अम्मा जानकी अम्मा**[10] के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है।

(19) कानूनी स्थिति को समझने के बाद अब निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 सितम्बर 1984 Ex. P 8 और P 9 को इंतकाल Ex. PW9/A दिनांक 2 दिसंबर, 1988 के साथ पढ़ा जाना आवश्यक है। ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के पृष्ठ 83 पर इन दस्तावेजों का अवलोकन, उदाहरण, इंगित करता है कि 20 सितंबर, 1984 के निर्णय और डिक्री दिनांक Ex. P 8 और P 9 के आधार पर। दीप चंद, प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में इंतकाल स्वीकृत किया गया है। यह आगे इंगित करता है कि इंतकाल आयत क्रमांक 116 (0–13M) के संबंध में स्वीकृत किया गया है। Ex. PW9/A की प्रासंगिक प्रविष्टियाँ यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है :-

पिछली जमाबंदी में प्रवेश / नई प्रविष्टि को अब प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है

मालिक का नाम विवरण सहित	खेतिहर का नाम साथ	खेत क्षेत्र की संख्या और नाम तथा मिट्टी का प्रकार	बिक्री और बंधक राशि के मामले में कीमत के साथ इंतकाल की

[9] (1996) 7 S.C.C. 389
[10] (2000) 7 S.C.C. 60

	विवरण		प्रकृति और तारीख (बंधक के मामले में)
9	10	11	13
दीप चंद पुत्र लिखी राम पुत्र छजवा 1/2 की सीमा तक दूसरों को पहले की तरह 1/2 शेयर की सीमा तक साझा करें	पहले की तरह शेयर : 1/2 शेयर 0-7 (लाल स्याही में)	116(मिनट) लाल स्याही 0-13 गैर मुमकिन	श्री पी.एल. गोयल, HCS Dवरिष्ठ उप न्यायाधीश की अदालत द्वारा पारित आदेशों के अनुसार स्वामित्व का हस्तांतरण।

स्वामित्व के हस्तांतरण के संबंध में इंतकाल को इसके वर्तमान स्वरूप SD/IAC II ग्रेड 2-12-1988 को मंजूरी दी गई है।

(20) नीचे दी गई अदालतें इस तथ्य पर विचार करने में विफल रही हैं कि 20 सितंबर 1984 के फैसले और डिक्री को आयत क्रमांक 116 (0–13M) के संबंध में राजस्व अधिकारियों से प्रतिवादी प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संशोधित कराया गया था। प्रतिवादी नंबर 1 दीप चंद के बयान के आलोक में उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए। अपनी जिरह में उसने स्वीकार किया है कि उसने आयत क्रमांक 116 (0–13M) में एक कमरा बनवाया है और निर्णय और डिक्री (Ex. P8 और P9) में सीमाएँ राजस्व का उल्लेख किया गया था क्योंकि

उस समय उन्हें संख्याओं की जानकारी नहीं थी। जाहिर तौर पर उपर्युक्त कथन के आधार पर आयत क्रमांक 116 (0–13M) के संबंध में इंतकाल Ex. PW9/Aको मंजूरी दी गई है। हालाँकि दस्तावेज़ों का उल्लेख नीचे के न्यायालयों द्वारा किया गया है, लेकिन इंतकाल Ex. PW9/A दिनांक 2 दिसंबर, 1988 को पढ़कर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है। पैरा 1, 4(ii) और 5 में 20 सितंबर, 1984 के निर्णय और डिक्री और इंतकाल Ex. PW9/A No. 1176 दिनांक 2 दिसंबर, 1988 का संदर्भ दिया गया है। उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर भी एक मुद्दा तैयार किया गया है। हालाँकि, उपर्युक्त दस्तावेज़ को पढ़ने में एक मूलभूत त्रुटि हुई है जिसके परिणामस्वरूप वादी-अपीलकर्ता के साथ स्पष्ट अन्याय हुआ है क्योंकि नीचे के न्यायालयों ने एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि भूमि की पहचान स्थापित नहीं की गई है जबकि फॉर्म में पर्याप्त सबूत हैं इंतकाल Ex. PW9/A , आयत संख्या 116 (0-13M) के संबंध में गैर मौरूसी आबादी भूमि के रूप में इंतकाल की मंजूरी को दर्शाता है और उसी भूमि पर वादी-अपीलकर्ताओं द्वारा दावा किया गया है। इसलिए, मुद्दा संख्या 1 पर नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के निष्कर्षों को खारिज किया जाना चाहिए।

(21) प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील का तर्क कि मलखान सिंह ने भूमि पर घर की उपस्थिति स्वीकार की है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मामले की दलीलों में, वादी-- पैरा 1 में अपीलकर्ता ने कहा है कि आयत संख्या 116 (0-13M) में उल्लिखित भूमि गैर मारुसी आबादी है। ऐसी प्रविष्टि को भूमि के सादे भूखंड के बजाय

आवासीय क्षेत्र के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए, वादी-अपीलकर्ता मलखान सिंह द्वारा PW 9/A के रूप में पेश होने पर की गई स्वीकारोक्ति पर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। अन्यथा भी Ex. PW 9/A के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य, किसी भी गवाह द्वारा दिए गए मौखिक बयान की तुलना में उचित महत्व दिया जाना चाहिए। पूर्वोक्त दस्तावेजी साक्ष्य Ex. PW9/A के रूप में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा समर्थित किया गया है जब वह DW 1 के रूप में उपस्थित हुआ था। उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि डिक्री Ex. P9 9 दिनांक 20 सितंबर, 1984 आयत संख्या 116 (0-13M) के संबंध में था। मुझे प्रतिवादी के विद्वान वकील की इस दलील में भी कोई दम नहीं दिखता कि तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इस नियम के अपवाद हैं और वर्तमान मामला उस अपवाद के अंतर्गत आता है जैसा कि कुलवंत कौर के मामले (supra) में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है।

(22) दूसरा तर्क कि स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति के लिए आवेदन में, वादी-अपीलकर्ता की विफलता को स्वीकार कर लिया गया है, किसी भी विस्तृत विचार की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आवेदन के पैरा 5 में केवल यही कहा गया है कि वादी-अपीलकर्ता उचित परिश्रम के बावजूद मुकदमे की संपत्ति को 20 सितंबर, 1984 के ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री में उल्लिखित संपत्ति के साथ जोड़ने में विफल रहे। इसलिए यह दावा किया गया कि उठाए गए मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति उचित होगी। आवेदन वकील के माध्यम से दायर किया गया है और एक हलफनामे द्वारा समर्थित है। यदि उपर्युक्त कथन

की जांच की जाती है तो यह नहीं माना जा सकता है कि यह स्वीकारोक्ति है कि मुकदमे में दावा की गई संपत्ति उस संपत्ति से अलग है जो आक्षेपित निर्णय और डिक्री Ex. P8 और P9 और इंतकाल Ex. PW9/A की विषय वस्तु थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 17, 18, 19, 20 और 21 के तहत किसी बयान को स्वीकारोक्ति के रूप में खारिज करने से पहले यह स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड पर स्थापित किया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाला बयान अपने हित के प्रति जागरूक होकर दिया गया था। बयान का प्रतिकूल असर आवेदन में दिए गए ऐसे कथन को स्वीकारोक्ति के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता। आवेदन में दिए गए कथन का प्रभाव केवल एक ही है अर्थात वाद भूमि के सीमांकन के लिए स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति की मांग का औचित्य प्रदान करना। किसी भी मामले में इस तरह के कथन को इस तथ्य की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है कि वाद भूमि निर्णय और डिक्री Ex. P8 और P9 और इंतकाल Ex. PW9/A उल्लिखित भूमि से भिन्न है। जो कुछ कहा गया वह यह था कि वह मुकदमे की भूमि को उस भूमि से जोड़ने में विफल रहा जो Ex. P8 और P9 और इंतकाल Ex. PW9/A की विषय वस्तु थी। इसलिए, उपर्युक्त निवेदन में कोई दम नहीं है और मुझे इसे अस्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

(22) ऊपर बताए गए कारणों से, यह अपील सफल होती है और दोनों न्यायालयों के निष्कर्षों को रद्द कर दिया जाता है। नीचे दिए गए न्यायालयों के निष्कर्षों को अलग रखा गया है। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 सितंबर, 1984 Ex. P8 और P9 के साथ-साथ इंतकाल Ex.

PW9/A को शून्य एवं अमान्य घोषित किया जाता है। वादी-अपीलार्थी के वाद का फैसला यह घोषित करते हुए किया जाता है कि वादी-अपीलकर्ता क्रमांक 1 एक शाश्वत पट्टेदार है और वादी-अपीलार्थी क्रमांक 2 वाद भूमि का स्वामी है। तदनुसार एक डिक्री तैयार की जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रितिज़ अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TRAINEE JUDICIAL OFFICER)